हमारी ओडीओपी योजना देश में यूनिक : योगी

यूपी का निर्यात 2 लाख करोड़ के पार, श्रमसाधकों का किया सम्मान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के हस्तशिल्पी, कारीगर व युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी। लाखों छोटी इकाइयां मौजूद थीं, लेकिन सरकारी उपेक्षा और इंस्पेक्टर राज के कारण उद्यमी पलायन को मजबूर थे।

2018 में ओडीओपी योजना शुरू की और परंपरागत उद्यम को मार्केट व टेक्नोलॉजी दी। आज हमारी ओडीओपी देश में यूनिक योजना बन चुकी है। हमारा निर्यात 86 हजार करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ का हो गया है।

सीएम बृहस्पतिवार को लोकभवन में इंटरनेशनल ट्रेड शो के कर्टन रेजर समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सीएम ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत बाराबंकी के राहुल (नाई), लखनऊ से निधि मल्होत्रा (दर्जी), सीतापुर के फिरोज अहमद (मोची) को सम्मानित किया। ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत रायबरेली के रंजीत कुमार (काष्ठ कार्य), लखनऊ की सरिता भारती (चिकनकारी), हरदोई की प्रतिभा यादव (वस्त्र उत्पाद) का सम्मान किया। माटी कला पुरस्कार के अंतर्गत गोरखपुर के कृष्ण कुमार प्रजापति (टेराकोटा), आजमगढ़ की पुष्पा प्रजापति (ब्लैक पॉटरी), सोनभद्र के धर्मू (मृदुभांड व नक्काशीदार फूलदान) का सम्मान किया। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत राज्यस्तरीय ग्रामोद्योगीय पुरस्कार से लखनऊ की शबाना खातून, मेरठ के शीषपाल, अमरोहा के कृष्णपाल को सम्मानित किया। ब्यूरो

13 परियोजनाओं का शुभारंभ

सीएम ने एमएसएमई क्लस्टर पार्क योजना के तहत रायबरेली, मऊ, प्रतापगढ़ व महोबा में औद्योगिक आस्थानों, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट स्कीम के तहत गोमतीनगर, लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेंटर, खाद्य एवं प्रसंस्करण के तहत कौशाम्बी में केला व गोंडा में दाल-मक्का में ओडीओपी सीएफसी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही, मिनी औद्योगिक आस्थान बिल्हौर कानपुर नगर, पचरावां रायबरेली व अयोध्या का उच्चीकरण, जिला उद्योग केंद्र कौशाम्बी, अमेठी और वाराणसी के नवीन भवनों का शिलान्यास किया।

पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण चुकाया तो 7.5 लाख रुपये का और ऋण देंगे

इस मौके पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि पांच लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण अदा करने वाले युवा उद्यमियों को 7.5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कहा, हरदोई-लखनऊ में बसाए जा रहे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए 200 करोड़ का प्रावधान बजट में है। केंद्र से भी 500 करोड़ जल्द मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जिले हैं, जहां की एक नहीं कई उत्पाद पहचान हैं। उन्हें भी ओडीओपी में शामिल करने की तैयारी है।